

गोपिंदर सिंह

बनाम

वन विभाग हिमाचल प्रदेश और अन्य

17 अगस्त, 1990

[एम. एच. कनिया और कुलदिप सिंह, जेजे.]

हिमाचल प्रदेश नौटोर भूमि नियम, 1968: नियम 7 (ए)-प्रति व्यक्ति 2,000 रुपये से अधिक वर्ष-की वैधता की आय वाले निवासी को नौटोर भूमि का अनुदान।

हिमाचल प्रदेश नौटोर भूमि नियम, 1968 के नियम 7 का खंड (ए) संपत्ति के प्रत्येक निवासी को दस बीघा से कम भूमि वाला बनाता है। भूमि या भूमि सहित सभी स्रोतों से 2,000 रुपये प्रति वर्ष से कम की आय, नौटोर में भूमि के अनुदान के लिए पात्र।

अपीलार्थी-शिक्षक को नौटोर भूमि का अनुदान वित्त आयुक्त द्वारा संशोधन में अलग रखा गया था। उच्च न्यायालय ने खारिज किया कि सीमा में रिट याचिका। विशेष अनुमति द्वारा की गई अपील में अपीलार्थी के लिए यह तर्क दिया गया था कि शब्द 'या' सी. एल. के पहले और दूसरे भाग के बीच में आता है। (क) नियम 7 का सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए और इसे 'और' के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि क्लोज के दो भाग, इसलिए, एक दूसरे के स्वतंत्र डेंट थे और उन्हें अलग-अलग पढ़ा जाना था, और यह कि वह पहले भाग के तहत पात्र है, भले ही एक शिक्षक के रूप में प्रति वर्ष 2,000 रुपये से अधिक की आय हो, लेकिन क्लू का दूसरा भाग (a) आकर्षित नहीं था।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि :

1. एक व्यक्ति जिसके पास 10 बीघा से कम भूमि है लेकिन जिसकी सभी स्रोतों से प्रति वर्ष 2,000 रुपये से अधिक की आय है। उक्त भूमि सी. एल. के तहत नौटर भूमि के आवंटन के लिए पात्र नहीं है। (क) हिमाचल प्रदेश नौटर भूमि नियम, 1968 के नियम 7 का। [800 जी]

2. नियमों के तहत नौटर भूमि देने का उद्देश्य राज्य के निवासियों के लिए गरीबों और गैर-प्रदत्त लोगों की मदद करना है। नियमों के निर्माताओं की प्रकृति, दायरे और स्पष्ट इरादे को ध्यान में रखते हुए खंड (ए) के पहले और दूसरे भाग के बीच 'या' शब्द को 'और' के रूप में पढ़ना आवश्यक है। इसलिए दोनों भागों को अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है। दूसरा भाग यह स्पष्ट करता है कि प्रति व्यक्ति 2,000 रुपये से कम की आय वर्ष भूमि सहित सभी स्रोतों से होना चाहिए। [800 एच; 801 ए]

3. तत्काल मामले में अपीलार्थी की आय उससे अधिक है। 2,000 रुपये प्रति वर्ष वह नौटर भूमि के अनुदान के हकदार नहीं थे। [801 ए]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 3006/1981 से।

प्रदेश उच्च न्यायालय हिमाचल के 1981 के सी.डब्ल्यू.पी. सं. 94 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 28.7.1981 से।

अपीलार्थी के लिए एम. वी. गोस्वामी।

उत्तरदाताओं के लिए निमो।

न्यायालय का निर्णय कुलदिप सिंह, जे द्वारा सुनाया गया।

हिमाचल के नियम 3 के तहत "नौटर भूमि" प्रदेश नौटर भूमि नियम, 1968 (जिसे इसके बाद 'नियम' कहा गया है) का अर्थ है सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ, शहरों के बाहर, सरकार के स्वामित्व वाली बंजर भूमि का उपयोग करने का अधिकार।

आरक्षित और सीमांकित संरक्षित वन, और ऐसे अन्य क्षेत्रों के बाहर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।

गोपींदर सिंह ने नौटर भूमि मापन अनुदान के लिए आवेदन किया। 14 कनाल गाँव में खेती के लिए 12 बीघा जमीन है। राजस्व सहायक चोपाल ने 29 जून, 1972 के अपने आदेश के अनुसार गाँव कनाल में स्थित 11 बीघा 1 बिसवा की रेत को एक करोड़ रुपये के भुगतान पर उन्हें सौंप दिया। 552.50 नजराना के रूप में। वन विभाग ने उक्त आदेश के खिलाफ उपायुक्त शिमला के समक्ष अपील दायर की जिसे स्वीकार कर लिया गया और राजस्व सहायक चोपाल के गोपींदर सिंह के पक्ष में नौटर भूमि को मंजूरी देने के आदेश को रद्द कर दिया गया।

गोबिंदर सिंह ने संभागीय आयुक्त को आगे की अपील दायर की। शिमला में हिमाचल प्रदेश ने इसे स्वीकार कर लिया और 9 सितंबर, 1974 के अपने आदेश के अनुसार गोपींदर सिंह को नौटर भूमि का अनुदान बहाल कर दिया। वन विभाग ने हिमाचल प्रदेश के वित्त आयुक्त (राजस्व अपील) के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिन्होंने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और 9 सितंबर, 1974 के संभागीय आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गोपींदर सिंह को नौटर भूमि की मंजूरी दी गई थी। उन्होंने आगे आदेश दिया कि नजराना की राशि गोपींदर सिंह को वापस कर दी जानी चाहिए और भूमि राज्य को फिर से दी जानी चाहिए। वित्तीय आयुक्त ने निम्नलिखित दो आधारों पर अपील स्वीकार कर ली:

- (1) गोपींदर सिंह ने बिना इंतजार किए पेड़ों को जमीन पर गिरा दिया। संभागीय वन अधिकारी के आवश्यक अनुमोदन के लिए और इस तरह उन्होंने कानून अपने हाथों में ले लिया।

(2) सरकारी स्कूल में मासिक ड्राइंग के शिक्षक होने के नाते Rs.650 अपराह्न से अधिक का परिलब्धि उनकी आर्थिक स्थिति यह उचित रूप से अच्छा था और इस तरह वह पात्र नहीं था। नियमों के तहत नौटर भूमि का अनुदान।

वित्तीय आयुक्त गोपींदर सिंह का आदेश दायर किया गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका शिमला में हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय जो निराशाजनक था। 28 जुलाई, 1981 को खदान। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील टी-वित्तीय आयोग के आदेशों के खिलाफ गोपींदर सिंह उच्च न्यायालय का

नियमों की धारा 7 में नौटोर लैंड का रेंट पात्र व्यक्तियों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। उक्त नियम इस प्रकार है:

"समुद्री भूमि के लिए पात्रता — विधवा और विधवा के लिए बचत करें बल, जिसने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है (जिसका विधवा और बच्चे कहीं भी अनुदान के पात्र होंगे। तहसील के भीतर उल्लिखित शर्तों के अधीन वाजिब-उल-अर्ज उन क्षेत्रों के संबंध में जहां भूमि लागू होती थी के लिए स्थित है) कोई भी जो संपत्ति में निवासी नहीं है जिसके लिए आवेदन की गई भूमि स्थित है, वह अनुदान की पात्र होगी। उस संपत्ति का प्रत्येक निवासी जिसमें भूमि है:

(ए) झूठ के लिए आवेदन निम्नलिखित क्रम में पात्र होगा वरीयताएँ: (क) ऐसे व्यक्ति जिनके पास दस बीघा से कम भूमि है, चाहे मालिक के रूप में, या किरायेदार के रूप में, या पट्टेदार के रूप में, या तो भारतीय प्रत्यक्ष या सामूहिक रूप से, या आय से कम है। भूमि सहित सभी स्रोतों से 2,000 रुपये प्रति वर्ष। बशर्ते कि इस श्रेणी में एक आश्रित है जिसके पास है देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपने समकक्षों पर वरीयता;

(बी) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदक;

(सी) उन लोगों के आश्रित जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। देश की रक्षा के लिए सेवा की। देश की रक्षा के लिए सेवा नागरिक की राजधानी में, जब तक मृत्यु एक पर होती है सामने, चाहे वह सैन्य हो या नागरिक;

(डी) सशस्त्र बलों और पूर्व सैनिकों में सेवारत कर्मी;

(ई) पंचायतें, और

(एफ) अन्य;

बशर्ते कि स्पीति का एक वास्तविक भूमिहीन निवासी होगा। स्पीति

उपखंड के भीतर नौटोर में भूमि अनुदान के लिए पात्र प्रभाग"।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने भरोसा किया है। नियम 7 के खंड (ए) के पहले भाग में यह दर्शाया गया है कि अपीलार्थी के पास 10 बीघा से कम भूमि थी और जो समुद्री भूमि के अनुदान के लिए पात्र था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि भले ही वह हो सकता है। एक शिक्षक के रूप में 2,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक की आय, वह पहले भाग के तहत पात्र, नियम 7 के खंड (ए) का दूसरा भाग है। अपने मामले में आकर्षित नहीं। उनके अनुसार प्रथम और द्वितीय भाग नियम 7 का खंड (ए) एक दूसरे के लिए स्वतंत्र है और वहाँ 'या' है। इन दोनों भागों के बीच इन्हें अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए। वह समझता है ऐसा लगता है कि 'या' को इसका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए और यह नहीं हो सकता है 'और' के रूप में पढ़ें। .

हमने नियम के खंड (ए) के प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच की है। 7 ऊपर पुनरुत्पादित। खंड में लिखा है "ऐसे व्यक्ति जिनके पास कम है 10 बीघा से अधिक भूमि. या जिनकी आय 2,000 रुपये प्रति एकड़ से कम है। भूमि सहित सभी स्रोतों से वार्षिक। इस प्रकार अंतर्निहित ईवीआई है खंड में ही यह दिखाने के लिए कि दोनों भागों को पढ़ा नहीं जा सकता है। अव्यवस्थित रूप से। दूसरा भाग यह स्पष्ट करता है कि कम आय

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति जिसे 10 बीघा से कम लैन मिला है लेकिन उक्त भूमि से 2,000 रुपये से अधिक की आय है, पात्र नहीं है खंड (ए) के तहत नौटर भूमि के आवंटन के लिए। अन्यथा भी अगर हम खंड की व्याख्या उसी तरह करें जिस तरह से अपीलार्थी का विद्वान वकील हमें चाहता है ऐसा करने से बेतुका परिणाम निकलेगा। एक व्यक्ति के पास दो बीघा जमीन होती है। लेकिन अन्यथा प्रति वर्ष Rs.20,000 अर्जित करना आवंटन के लिए पात्र होगा। यदि हम अपीलार्थी की व्याख्या को स्वीकार करते हैं। नियमों के तहत नौटर भूमि देने का उद्देश्य गरीबों की मदद करना और हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए प्रदान नहीं किया गया। इसे ध्यान में रखते हुए नियमों के निर्माताओं की प्रकृति, दायरा और स्पष्ट इरादा यह है कि खंड (क) के पहले और दूसरे भाग के बीच "या" शब्द को "और" के रूप में पढ़ना आवश्यक है। अपीलार्थी की आय 2,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक थी और इस प्रकार नौटर भूमि के लिए उसके दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

इसलिए हम अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों से सहमत नहीं हैं। इसलिए, अपील को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

याचिका खारिज कर दी गई।

पी.एस.एस.